(Rs. in lakhs

Purpose	1994-95	1995-96	1996-97
Investment Credit	17726	18898	22456
Short Term Refinance	25310	25651	31162
. Medium Term Refinance			16
Loans provided to State Government for sh ire capital assistance to cooperative institutions	620	188	..

(b) The data reportng systems of RBI and NABARD do not generate this in formation.

Finarfcittg of SelJ-Eniployment Schemes by Commercial Banks in North-Easteni Regjon

2212, SHRl W. ANGOU SINGH: Will the Ministea- of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Commercial bank working in the North-Eastern States are not properly fmancing the self-employment schemes;

(b) the commercial banks loans target and achievements during the Eighth Five Year Plan in the regioa of North-East on State-wise basis; and

(c) if the commercial banks are reluctant in financing the self-employment sc-. hemes what alternate arrangement are contemplated by Governmenft or implementing the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAT-PAL MAHARAl): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Hbuse.

प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन

2213.**श्री राम जेठमलानी**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के संबंध में प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा क्या हैं; और

(ग) परिभाषा में संशोधन करके उसमें नये क्षेत्रों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी,नहीं।

(ख) और (ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में निम्नलिखित शामिल है:

(i) कृषि

(ii) लघु उद्योग

(iii) लघु सड़क एंव जल परिवहन चालक

(iv) लघु व्यवसाय

(v) खुदरा व्यापार

(vi) व्यावसायिक और स्वत: नियोजित व्यक्ति

(vii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों सहित कमजोर वर्ग।

(viii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन

(ix) शिक्षा

(x) आवास

(xi) उपभोग

(xii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जाने वाली निधियां

(xiii) स्वंय सहायता समहों को ऋण

(xiv) एस एफ सी एस आई डी सी डी.आई ई सी,नाबार्ड तथा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष बांडों में अशंदान।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण वर्गो के अन्तर्गत कमजोर वर्गो एंव लघु उधारिकर्ताओं की सहायता करना है । इसलिए,अन्य वर्गो को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गा है क्योंकि उन्हें शामिल किए जाने से प्राथमिकता क्षेत्र के वर्तमान घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Licencing of Private Skcitor Banks

2214. SHRI K. RAHMAN KHAN:

Will the Minister of FINANCE pleased be to state:

(a) the number of private sector banks that have been licensed so far;

(b) the numberof applications for bank license that have been given approval in principle and the names of the applicants;

(c) the number of applications that are pending and whether Government will consider the application and the names of the applicants pending; and '

(d) since when the applications for licences are pending and the reason it-delaying the decisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAT-PAL MAHARAJ): (a) Reserve Bank of India (RBI) have reported that there are at present 35 Indian private sector banks functioning in the country out of which 34 are licenced bank, the only exceptioni' being the Sikkim Bank Ltd.

(b) RBI had also granted 'in-principle'* approval to thres applicants to set up new banks in the privste sector. However, tv/o of these 'in-prlnicple' approvals have since been withdrawn.

(c) According to RBT, 40 applications have been received by them for setting up of new banks in ths private sector.

(d) The experience gained with reference to the functioning of new private sector banks over a reasonable period of time and the merit of the application as also the needs of the system will determine further licensing decisions and as such no time frame can be fixed for e-cisions on these applications.

निजी बैंक

2215.**श्री नागमणि**:क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र में स्थापित किये गये ऐसे बैंकों के नाम क्या-क्या है जिनकी स्थापना को तीन वर्ष से अधिक समय बीच चुका है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के उन बैंकों द्वारा ग्रामीण्ण तथा अर्द्व शहरी क्षेत्रों में रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार शाखाएं खोली जा रही हैं; और

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?